नवदुनियाँ, भोपाल

3 JAN 2015

मुख्यमंत्री ने नीति आयोग का किया स्वागत

भोपाल (ब्यूरो)। केन्द्रीय योजना आयोग की जगह नेशनल इंस्टीटयूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया (नीति) आयोग के गठन से देश के विकास में बदलाव दिखेगा। इस आयोग के गठन से राज्यों के साथ धन आवंटन को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए आयोग का स्वागत करते हुए ब्लाग और ट्विटर के माध्यम से कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2015 की नई सुबह केंद्र ने सहकार और लोकतांत्रिक मूल्यों आधारित विकास के नए युग में आंखें खोली हैं। 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के चहुंमुखी विकास के लिए जिस योजना आयोग का गठन किया था, वह उस दौर की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के संदर्भ में ठीक था। आजादी के बाद देश का जो विकास हुआ उसमें आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद योजना आयोग की प्रासांगिकता लगातार खत्म होती चली गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र में सत्ताधारी दल के राजनीतिक हितों के संवर्धन में आयोग के राज्यों के साथ राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह सहायक होने लगे थे। धनराशि के आवंटन में इसी कारण राज्यों के साथ भेदभाव की बात तीव्रता से महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था में ग्राम स्तर पर योजनाएं तैयार करने की पहल बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में उन्होंने यह काम पहले ही कर लिया है। प्रदेश के गांवों के विकास के लिए मास्टर प्लान ग्रामीणों के सुझाव, सहमति और भागीदारी से बनाए गए हैं।